ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल का.....

पेज एक का शेष

प्रोफेसरों को एक-एक साल के लिये रखा जाता है। कमी पूरी न होने पर कुछ प्रोफेसर 44-44 दिनों के लिये ठेके पर भी रखने पड़ते हैं।

इतना ही नहीं, कॉर्पोरेशन की फेकल्टी विरोधी नीतियों के चलते अधिकतर प्रोफेसर साहेबान बेहतर सेवा शर्तों के चलते अन्य संस्थानों की ओर जाने को प्रयत्नशील रहते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी द्वारा चयनित फार्माक्लॉजी व मेडिसन विभाग से तीन प्रोफेसर पलायन कर चुके हैं तथा शीघ्र ही सर्जरी व ईएनटी विभाग से भी प्रोफेसरों के पलायन की तैयारी है। सवाल यह पैदा होता है कि कॉर्पोरेशन को, किसी भी अन्य संस्थान से बेहतरीन सेवा शर्तें प्रदान करने में क्या मौत पड़ रही है? और तो और पिछले दिनों तो फेकल्टी के तबादलों का भी चर्चा चला कर उन्हें परेशानी में डाल दिया गया था।

यदि जानकार सूत्रों की मानें तो, इन हालात से परेशान होकर गत माह डीन ने कॉर्पोरेशन को तीन माह का नोटिस देकर सेवा निवृति मांगी है। अब देखना है कि कॉर्पोरेशन अपने रवैये एवं कार्यशैली में वांछित सुधार करती है अथवा डीन साहब को रुखसत करती है।

चिंतन शिविर तो सरकार करती है पर धरातल पर काम नहीं

बीते माह ईएसआई कॉर्पोरेशन ने सूरजकुंड के निकट स्थित एक पंचतारा होटल ताज विवांता में दो दिन का चिंतन शिविर 17-18 अगस्त को आयोजित किया था। इसमें कॉर्पोरेशन के तमाम अस्पतालों के डीन व चिकित्सा अधीक्षकों को आमंत्रित करके चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर एवं विस्तृत करने पर विचार विमर्श किया गया था। इसमें निगम के डीजी सहित तमाम उच्चाधिकारी शामिल थे।

शिविर के दूसरे दिन केन्द्रीय श्रम मंत्री व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा उनके मंत्रायलों के उच्चाधिकारी भी शामिल हुए थे। इन बैठकों से अनुमान लगाया जा रहा था कि मोदी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं खास कर ईएसआई द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कोई मूल-चूल परिवर्तन करने वाली है। इस शिविर के तुरन्त बाद 25-26 अगस्त को तिरुपति में तमाम राज्यों के श्रम मंत्रियों व उनके सचिवों को बुलाकर, उनके द्वारा दी जा रही ईएसआई चिकित्सा सेवाओं पर विचार विमर्श किया गया।

बेशक धरातल पर अभी कुछ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन समझा जाता है कि मोदी सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ चिंतित तो है। वर्ष 2018 में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जिस आयुष्मान योजना का ढोल पीटा गया था उसकी विफलता को ढकने के लिये सरकार कुछ न कुछ उपाय खोजने में लगी है।

आईसीयू की आवश्यकता और तमाशा

कोविड काल के दौरान कॉर्पोरेशन अधिकारियों की जब नींद खुली तो उन्हें पता लगा कि अस्पतालों में जिंदगी बचाने के लिये आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) की भी आवश्यकता होती है। उस वक्त कॉर्पोरेशन के अधिकांश अस्पतालों में यह सुविधा नहीं थी। फ़रीदाबाद वाले अस्पताल में भी मात्र 30 बेड के आईसीयू यूनिट को ठेके पर देकर कॉर्पोरेशन ने अपना पल्ला झाड़ रखा था। लेकिन वास्तविक जरूरत पड़ने पर ठेकेदार भाग खड़ा हुआ।

कोविड काल के अनुभव को देखते हुए कॉर्पोरेशन ने अपने हर अस्पताल में आईसीयू बनाने का निर्णय लिया। नियमानुसार किसी भी अस्पताल के कुल बिस्तरों के 10 प्रतिशत के बराबर आईसीयू बेड होनी चाहिये। इस हिसाब से फ़रीदाबाद में 50 बेड का आईसीयू तो है लेकिन इसके लिये आवश्यक स्टाफ़ नहीं दिया गया।

विदित है कि आईसीयू में मरीज की पूरी देख-रेख खुद अस्पताल को ही करनी होती है। इसके लिये प्रत्येक मरीज़ के साथ एक नर्स अथवा नर्सिंग अर्दली रखा जाता है। कार्पोरेशन ने इसके लिये आज तक एक भी पद स्वीकृत नहीं किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आईसीयू कैसे चलती होगी।

पीने के दूषित पानी की सप्लाई से परेशान जनता ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन

करनाल (रवि भाटिया) गोविंदपुरा और चांद सराय के लोगों ने पीने का पानी की दूषित सप्लाई होने से नाराज होकर सडक़ पर जाम लगाकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा पीने के पानी को लेकर काफी समय से परेशान है, लेकिन शिकायतों क बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पीने के पानी में रेत के साथ-साथ कीड़े आ रहे हैं। लोग परेशान व निराश है।

ऐसे हालात में लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। लोगों की परेशानी की तरफ ना तो प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही वार्ड का पार्षद आकर उनकी समस्या सुन रहा है। पानी के बिना छोटे-छोटे बच्चे प्यासे बिलख रहे हैं। पानी की समस्या को हल नहीं किया तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। महिलाओं और लोगों ने विरोध स्वरूप जाम लगा कर रोष जताया। बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग जाम को खोलने के लिए राजी हुए।

प्रदर्शन कर रहे लोगों में सुरेन्द्र सैनी, सुनीता व राजू ने बताया कि काफी समय से चांद सराय व गोविंदपुरा के लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। इस क्षेत्र में पानी इतना खराब आता है कि न तो पानी को पी सकते और न ही उस पानी से नहाया जा सकता। कई बार पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब लोग कहा जाए और क्या करें। जब सीएम सिटी के लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा, तो ऐसी सरकार किस काम की है।

सड़कों पर अवैध पार्किंग नज़र क्यों नहीं आती डीसीपी को ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) अच्छी बात है कि डीसीपी ट्रैफ़िक नीतीश कुमार अग्रवाल को बाटा मोड़ से दिल्ली की ओर यू-टर्न लेने वालों की समस्या तो नज़र आई। इससे निपटने के लिये उन्होंने अपने स्तर पर बैरिकेडिंग के द्वारा इस समस्या को हल करने में कुछ तत्परता दिखाई। इस बैरिकेडिंग में एक खतरे की ओर शायद उनका ध्यान नहीं गया। रात के समय यह बैरिकेडिंग बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि यदि इस पर रिफलेक्टर भी लगा दिये जायें।

बाटा पुल से राजमार्ग की ओर उतर कर दिल्ली की ओर जाने वालों के रास्ते को जिस प्रकार से ऑटो तथा अन्य वाहनों ने घेर कर रोका होता है उस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार पुल से उतर कर जब बल्लबगढ़ की ओर चलते हैं तो राजमार्ग पर खड़े रहने वाले ऑटो यातायात में बाधा पैदा करते हैं। इस प्वाइंट पर सर्विस लेन होने के चलते तमाम ऑटो वालों को इस लेन से गुजार कर राजमार्ग को जाम से बचाया जा सकता है। बल्लबगढ़ से बाटा की ओर आने वाले वाहनों की कठिनाई को, उस रास्ते पर सदैव खड़े रहने वाले वाहनों ने काफ़ी बढ़ा रखा है। वहां से अवैध पार्किंग को हटाने से काफ़ी राहत मिल सकती है।

लगाभग यही स्थिति अजरोंदा मोड़ व ओल्ड फरीदाबाद चौक की है। अजरोंदा मोड़ पर डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय होने के बावजूद, आसपास की सड़कों पर अवैध पार्किंग से लगने वाले जाम काफ़ी निराशा उत्पन्न करते हैं। कभी फ़ुर्सत मिले तो डीसीपी स्वयं इन सड़कों को घेरे खड़े वाहन चालकों से पूछताछ तो करें।

बाटा पुल से उतर कर हार्डवेयर चौक की ओर जाते हुए तथा इसी चौक से बाटा की ओर आते हुए, दोनों सड़कों पर बड़े-बड़े ट्रक व ट्राले सड़क पर कब्जा जमाये रहते हैं। यह ठीक है कि ये वाहन वहां स्थित स्टीलयार्ड से माल लाने-ले जाने को आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि वे आम नागरिकों की सड़क ही कब्जा लें। पुलिस के इस ढुलमुल रवैये से उत्साहित होकर, राजमार्ग से सेक्टर 15 की ओर जाने वाली सड़क पर खुलने वाले स्कॉर्ट प्लांट के गेट के सामने भी ट्रकों की लम्बी लाइने लगने लगी हैं। इससे भी बद्तर हालत इंडियन ऑयल के सामने वाली सड़क की है जहां पर फोर्ड ट्रैक्टर कंपनी का माल लादे पचासों वाहन हर समय खड़े रहते हैं।

एक-दो चोक को ऑटो रिक्शाओं द्वारा लगाये जाने वाले जाम से मुक्त कराने के लिये किया गया प्रयास भी कुछ हद तक सराहनीय है। ऐसे ही प्रयास अन्य स्थानों पर भी किये जाने की जरूरत है।

घोटालों का शहर बना सीएम सिटी

गरीबों का राशन डकार रहे लुटेरे

करनाल (जेके शर्मा) भाजपायी सीनियर डिप्टी मेयर के डिपो होल्डर का भाई द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का मामला अभी थमा नहीं कि करनाल में फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर सरकारी राशन हड़पने का खुलासा हो गया। नगर निगम के एससी, पूर्व तहसीलदार राजबख्श, डीटीप विक्रम, एचएसवीपी का जेई और सीनियर डिप्टी मेयर के भाई द्वारा फर्जीवाड़े के बाद सीएम सिटी को घोटाले की सिटी कहा जाने लगा है।

नए मामले में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में अधिकारियों ने डिपो होल्डर के संग मिलीभगत करके करीब 966 फर्जी बीपीएल कार्ड बना डाले। लाखों रुपए का राशन घोटाला सामने आने पर डीएफएससी ने जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए। खास बात यह है कि पारदर्शिता का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों सहित सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है।

सिटी के सरकारी विभागों में घोटालों की बढ़ती लिस्ट का परिणाम है कि रविवार को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री यहां चंद मिनट मीडिया कर्मियों को देने की बजाए पिछले दरवाजे से निकल गए। हालात जैसे भी हों, लेकिन प्रदेश सरकार की पारदर्शिता पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि बिना राजनीतिक शह के एक रुपए का फर्जीवाड़ा संभव नहीं है, फिर करनाल में 5 माह से रोजाना कोई न कोई बड़े घोटाले का खुलासा कई सवाल खड़े करता है।

ऐसा नहीं है कि विभाग में फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने का यह कोई पहला मामला सामने आया है। इससे पहले भी 100 से अधिक फर्जी बीपीएल कार्ड पकड़े जा चुके हैं। इन फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने वाले डिपो होल्डर सहित विभाग के इंस्पेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी इंस्पेक्टर व डिपो होल्डर जेल की हवा खा रहे हैं, बावजूद इसके फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने का खेल जारी है।

करोड़ों का राशन घोटाला.. अधिकारी क्यों नहीं रखते निगरानी

अब सवाल यह उठते हैं कि सीएम सिटी होते हुए भी पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए के राशन घोटाले हो चुके हैं। घोटालों को लेकर खुलासे तो होते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। अधिकारी हर बार यह कह कर टाल देते हैं कि उनके द्वारा कमेटी गठित की गई है, जो जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट जब तक आती है, मामला ठंडा हो जाता है और जांच भी कागजों तक सीमित रह जाती है। अगर इन घोटालों को रोकना है तो अधिकारियों को निगरानी रखनी होगी।

फर्जी बीपीएल कार्ड पकड़े जाने पर.. कैसे जारी रहता राशन

बता दें कि जिन भी डिपो होल्डरों के यहां द्वारा फर्जी बीपीएल कार्ड पाए जाते हैं, विभाग की तरफ से उन डिपो धारकों की सप्लाई सस्पेंड कर दी जाती है। उस डिपो का राशन दूसरे डिपो पर भेज दिया जाता है। उसके बाद भी उन फर्जी बीपीएल का राशन बंद नहीं किया जाता।

सीनियर डिप्टी मेयर के डिपो होल्डर भाई की जांच ठंडे बस्ते में

बता दें कि बीते दिनों सेक्टर 32-33 थाना में सीनियर डिप्टी मेयर के डिपो होल्डर भाई भारत भूषण पर डीएफएससी विभाग द्वारा एक शिकायत की जांच के बाद 44 फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक जांच में क्या सामने आया, इसकी जानकारी लोगों के सामने नहीं आई है। वहीं इन घोटालों को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं की तरफ से इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

30 डिपो पर 966 फर्जी बीपीएल कार्ड

मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यालय के और से जारी निर्देशों के अनुसार विभाग की ओर से पीपीपी में दर्ज आय और नाम के आधार पर राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को चयनित करके ऑनलाइन डाटा का मिलान किया गया। ऑनलाइन डाटा के आधार पर जिलेभर के करीब 30 डिपो होल्डरों पर 966 फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बने होने की बात सामने आई है। ऐसे में अब इन 30 डिपो धारकों पर गाज गिर सकती है।

करनाल DFSC कुशल पाल बुरा ने बताया कि पिछले दिनों पहले विभाग की ओर से परिवार पहचान-पत्र में दी आय के आधार पर संबंधित नामों की सूची उनको सौंपी गई थी। विभाग के आदेशानुसार, जिले के सभी खंडों में उनके द्वारा पीपीपी में दर्ज आय और नाम के आधार पर मिलान किया गया, जिसमें 966 फर्जी बीपीएल कार्ड 30 डिपो पर पाए गए हैं। इन बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। इनकी जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जैसे ही कमेटी की जांच रिपोर्ट आती है, उसे मुख्यालय भेजा जाएगा, उसके बाद ही बनती कार्रवाई की जाएगी।